रणजीत टाइम्स

RNI - NO. MPHIN/2015/64585

वर्ष- 11 अंक - 54 साप्ताहिक अख़बार

इंदौर प्रति मंगलवार , 18 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक पृष्ठ - 8 मूल्य - 2 रू.

बाघ पंचायत क्षेत्र में

बगैर अनुमति के हो रहे... अवैध निर्माण

आदित्य शर्मा, 8224951278

जल्द रणजीत टाइम्स द्वारा किया जाएगा खुलासा

इंदौर। ग्राम पंचायत बाघ में कई अवैध निर्माण किया जा रहा हे न ही उन निर्माणों की अनुमति हे न ही परमिशन जब हमारे द्वारा छानबीन की गई तो पता लगा हे कि न ही इन भवन निर्माण की अनुमति ली गई न ही इन निर्माणों की सूचना सरपंच और सचिव को अब देखने वाली बात हे कि बाघ पंचायत में ऐसे अवैध निर्माण कब तक होते रहेंगे कब प्रशासन इन अवैध निर्माणों पर संज्ञान लेगा या ये अवैध निर्माण ऐसे ही होते रहेंगे ।जब हमारे द्वारा रहवासियों से चर्चा करी तो पाया गया कि यह निर्माण बहुत दिनों से चल रहा हे जिसपे न ही शासन की नजर गई हे न ही प्रशासन की अब जल्द ही रणजीत टाइम्स द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर प्रशासन को मामले से अवगत कराएगा एवं उचित कारवाही की मांग करेगा अब देखने वाली बात यह होगी प्रशासन इस मामले पर किस तरीके से कारवाही करता है।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

छत्रपति शिवाजी महाराज

स्वराज्य के शिल्पकार और राष्ट्र के प्रेरणास्रोत

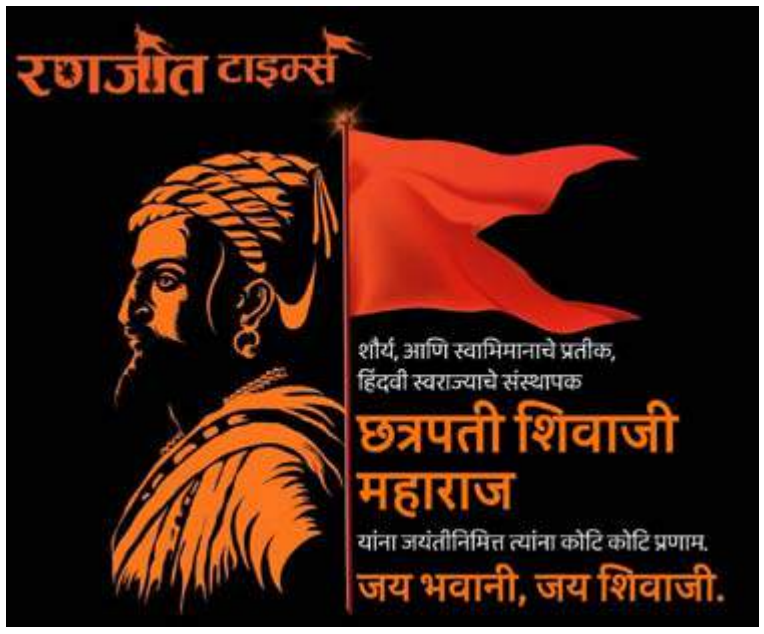

संपादक गोपाल गावंडे

रणजीत टाइम्स

भारत के स्वर्णिम इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं और कुशल शासकों ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान सबसे अलग और सर्वोच्च है। वे न केवल एक अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, महान रणनीतिकार और स्वराज्य के प्रणेता भी थे। उनकी जयंती हमें उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा देती है।

स्वराज्य की अवधारणा और शिवाजी महाराज का संकल्प

शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाकर राष्ट्र और धर्म की रक्षा का संकल्प दिलाया। यही कारण था कि वे एक बालक के रूप में ही अन्याय और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध खड़े हो गए। "हिंदवी स्वराज्य" की स्थापना उनका मुख्य उद्देश्य था, जो किसी विशेष जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए था।

रणनीति और युद्ध कौशल

शिवाजी महाराज ने भारत में पहली बार छापामार युद्धनीति (गुरिल्ला वॉरफेयर) को अपनाया। यह नीति इतनी प्रभावी थी कि बड़े-बड़े मुगल और आदिलशाही सेनानायक भी उनसे हार गए। अफजल खान वध, सूरत की लूट, पन्हाला और रायगढ़ दुर्ग की विजय उनकी सैन्य रणनीति के अद्भुत उदाहरण हैं। उन्होंने नौसेना को भी सशक्त किया और भारतीय समुद्र तटों की रक्षा के लिए सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और सुवर्णदुर्ग जैसे किलों का निर्माण करवाया। यही कारण है कि वे "भारतीय नौसेना के जनक" भी कहे जाते हैं।

शासन व्यवस्था और लोक कल्याणकारी नीतियाँ

शिवाजी महाराज केवल युद्ध तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक संगठित और न्यायसंगत प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। उनकी शासन नीति में धार्मिक सहिष्णुता, किसानों और व्यापारियों का संरक्षण, महिलाओं का सम्मान और कमजोर वर्गों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई। उनकी कर-प्रणाली सरल थी और वे जनता से जबरन धन वसूलने के सख्त विरोधी थे। यही कारण था कि उनके शासन में जनता उन्हें राजा नहीं, "राजा पिता" कहकर संबोधित करती थी।

आधुनिक भारत के लिए शिवाजी महाराज की प्रासंगिकता

आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें आत्मसम्मान, परिश्रम और रणनीतिक सोच की सीख देता है। उनकी नीतियाँ केवल मराठा साम्राज्य तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रासंगिक हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र, समाज और संस्कृति की रक्षा और उन्नति के लिए कार्य करेंगे।

"जय भवानी! जय शिवाजी!"

ग्वालियर में पुजारी की एक माह बाद इलाज के दौरान मौत

परिजनों ने आरोपियों के नाम बढ़ाकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की

रणजीत टाइम्स-ऋषि गोस्वामी

शिवपुरीः जिले के बेहरावदा गांव में 17 जनबरी को मंदिर के पुजारी वीरेंद्र शर्मा उम्र 40 साल पर जानलेवा हमला कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने कन्हैया यादव पर मामला दर्ज कर लिया था. आज परिजनों ने एफआईआर में आरोपियों के नाम बढ़ाने को लेकर एसपी ऑफिस पर धरना शुरू कर दिया हैं।

बता दें की 17 जनबरी को गांव के कन्हैया यादव के परिवार ने पुजारी वीरेंद्र शर्मा को चाय पर बुलाया था। वहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद पुजारी पर हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल पुजारी को पहले शिवपुरी जिला अस्पताल लाया गया और फिर हालत नाजुक होने पर ग्वालियर रेफर कर दिया गया था. आज एक माह बाद पुजारी बीरेंद्र शर्मा का ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई हैं. पुजारी के शव को परिजन एंबुलेंस से शिवपुरी लेकर आए जहां उन्होंने एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं. परिजनों की मांग है कि एफआईआर में केवल कन्हैया यादव का नाम ही लिखा गया था जबकि आरोपियों में दखनलाल, धनीराम पुत्र परमाल एवं जानकी पत्नी परमाल का नाम भी शामिल होना था. परिजनों ने एफआईआर में नाम बढ़ाने की मांग की हैं।

सामाजिक समस्याओं को फेसबुक नहीं फेस टू फेस बैठकर सुलझायें : गोपाल पाल

रणजीत टाइम्स-जगदीश पाल

हम चाहते हैं नेता हमारे घर में पैदा हो भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा ऐसे नहीं होगा समाज का विकास : लाखन सिंह

पिछोर विधानसभा के ग्राम हीरापुर बडैरा में सिद्धबाबा मंदिर पर पाल बघेल धनगर समाज का सामाजिक सम्मेलन संपन्न

शिवपुरी। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि आपसी सामाजिक विवादों को सोशल मीडिया पर न उछालें, समस्याओं को फेसबुक पर नहीं फेस टू फेस बैठकर निपटानी चाहिए, हमें अपने भाईयों की टांग न खींचते हुए उसके हाथ को खींचना होगा। हमें समाज को अपनी समाज को मां स्वरूप मानना चाहिए जिस तरह हम अपनी मां की कभी बुराई न करते हैं न सुनते हैं इसी तरह हमें समाज की बुराई न करनी चाहिए न सुननी चाहिए यह बात पाल बघेल धनगर समाज के प्रदेशाध्यक्ष इंजी. गोपाल सिंह पाल ने पिछोर विधानसभा के ग्राम हीरापुर बडैरा में सिद्धबाबा मंदिर (कपूरखो) में आयोजित विधानसभा स्तरीय सामाजिक सभा में कही। सभा को पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल ने भी संबोधित करते हुए कहा कि यह चाहते हैं कि नेता हमारे घर में पैदा हों और भगत सिंह सामने वाले के घर में पैदा हो हमें यह सोच छोडनी होगी हमें ही नेता और भगत सिंह दोनों पैदा करने होंगे, हमे हमारे इतिहास से सीखना होगा, जिस पराक्रम और साहस के दम पर हमारे पूर्वजों ने शासन किया उसी तरह हमें अपने आपको को क्रांतिकारी विचारों में ढालना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिटायर्ड डीएसपी मदन पाल ने कहा आप नकारात्माक बातों को त्याग कर सकारात्मक बातों को ग्रहण करो, आप जहां हो वहां अपनी अच्छी छवि बनायें, अच्छे काम करें समाज का विकास होगा। सभा को पाल बघेल धनगर समाज के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रामस्वरूप बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें अगले चुनावों से पहले गांव गांव में जाकर समाज की बैठकें करनी पडेंगी और समाज को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना होगा हम हर विधानसभा के जिताने और हराने की भूमिका रखते हैं हमें नजरअंदाज करना अब प्रमुख पार्टियों को भारी पडेगा। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. रामगोपाल बघेल हरी प्रिंस द्वारा किया गया। कार्यक्रम को रामसेवक पाल, जिला पंचायत सदस्य हेमलता हरिकृष्णे बघेल, युवा जिलाध्यलक्ष शिशुपाल सिंह बघेल, विधानसभा प्रभारी राजकुमार पाल, मण्डल अध्यक्ष मेहरबान सिंह बघेल, नेपाल सिंह बघेल रतिराम पाल ,करन पाल,आनंद पाल, पंजाब सिंह बघेल, रामनिबास बघेल चिन्नोदी, अशोक पाल, ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शोभाराम पाल द्वारा किया गया।

खनियाधाना क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच में पंजाब ने चंबल टाइगर को हराया

रणजीत टाइम्स-जगदीश पाल

अखिल भारतीय राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट सिलपुरा ग्राउंड में संपन्न हुआ

शिवपुरी (खनियाधाना) आज के मैच में एक तरफ मैच पर पंजाब ने चंबल टाइगर को हराकर टूर्नामेंट की विजेता टीम बनी विधायक कप खनियाधाना में सिलपुरा ग्राउंड पर अखिल भारतीय राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का समापन हुआ टूर्नामेंट में आज जिस प्रकार से पब्लिक मैच को देखने आई वास्तव में रोड पर महा रैली जैसा लग रहा था वही ग्राउंड की सारी व्यवस्था विधायक पुत्र राकेश भैया और दिनेश भैया ने संभाली आयोजन समिति में विवेक यादव मंडल अध्यक्ष भाजपा भानु जैन विधायक प्रतिनिधि रईस यादव विधायक प्रतिनिधि रमाकांत पाठक दबंग नेता सरदार सिंह परिहार विधायक प्रतिनिधि कोठादार साहब विधायक प्रतिनिधि अभिषेक साहब विधायक प्रतिनिधि मुकेश चौधरी पिछोर विधायक प्रतिनिधि अजय झा सनातन विजयपाल बलवीर राजपूत शैलेंद्र गुप्ता मीडिया प्रभारी टूर्नामेंट सभी ने शानदार मैनेजमेंट करके टूर्नामेंट को सफल बनाया पुरस्कार वितरण आदरणीय पहलाद सिंह जी यादव भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं राजू बाथम जी पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष और राकेश भैया ने विजेता और विजेता और मैन ऑफ द मैच एवं मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार वितरण किया दर्शकों के लिए भी शानदार बलवीर राजपूत आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम भी रखा गया था जो पब्लिक को मनोरंजन की दृष्टि से पूरे समय तक बांधे रखा।

फाइनल टूर्नामेंट खतौरा में स्व. श्री रामसिंह यादव दादा स्मृति चल रहे टूर्नामेंट मै कल मैन ऑफ द मैच बारोद इलेवन विवेक मीणा को मिला खतौरा काफी समय से चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें आज मुख्य अतिथि थाना प्रभारी ईन्दार दिनेश नरवरिया

शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा के खतौरा में फाइनल टूर्नामेंट खतौरा में कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव के पिताजी स्व. रामसिंह यादव (दादा) स्मृति चल रहे टूर्नामेंट मै मैन ऑफ द मैच बारोद इलेवन विवेक मीणा को मिला खतौरा काफी समय से चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें कल मुख्य अतिथि थाना प्रभारी ईन्दार दिनेश नरवरिया दुर्जन सिंह यादव एवं समस्त मंच अतिथि गढ़ उपस्थित रहे।

फाइनल मुकाबले मे आर्यन इलेवन सजाई V/S बरोद इलेवन के बीच मे खेला गया जिसमे आर्यन इलेवन विजेता टीम रही और बरोद इलेवन उपविजेता रही। अतिथियों द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी,1 लाख 1 हजार का चैक व मैन ऑफ़ द सीरीज को LED TV एवं उपविजेता टीम को अतिथियों द्वारा 51000 हजार का दिया गया जिसमें सेमी फाइनल मैच शिवपुरी पुलिस लाइन एवं बारोद इलेवन के बीच मुकाबला बहुत ही शानदार हुआ जिसमें बारोद इलेवन ने पहले टॉस जीत कर गेंदबाजी की शिवपुरी पुलिस लाइन ने जब बैटिंग की जिसमें उन्होंने 137 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की बारोद इलेवन उसका लक्ष्य का पीछा करते हुए कल सेमी फाइनल खतौरा में बारोद इलेवन ने 138 रन बनाकर बहुत ही अच्छी जीत हासिल की और इस बीच, शिवपुरी पुलिस लाइन एवं बारोद इलेवन के बीच हो रहे बड़े ही मुकाबले के साथ कल क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं बंधन स्वर्गीय राम सिंह यादव दादा की याद में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट खतौरा में जिसमें अहम भूमिका निभाने वाले अनेश यादव कमेटी सदस्य हरिओम किरार दानवीर यादव रामपाल यादव राहुल यादव सौरभ पेंटर नीरज कुशवाहा बिट्टू भैया चंद्र कुमार जैन अनिल कुमार गुप्ता रितिक यादव जसवंत किरार रिंकेश कुशवाहा कोमेंटेटर ब्रह्मा भार्गव रंजीत परिहार आरिफ खान।

मोबाइल टावर लगने के विरोध में रहवासियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

पीथमपुर। विश्वास नगर में मोबाइल टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है इस पर विश्वास नगर रहवासियों ने विरोध जताया की मोबाइल टावर रहवासी क्षेत्र में ना लगाया जाए। टावर लगाने से उससे फैलने वाला रेडिशन से लोगों के स्वास्थ्य पर बूरा प्रभाव पड़ेगा। इसे रहवासी क्षेत्र छोड़कर कहीं ओर आउटर एरिया में लगाया जाए। इस संबंध में विश्वास नगर के जनपद सदस्य संग्राम सिंह राजे भोसले और विश्वास नगर के रहवासियों ने बुधवार को विधायक उषा ठाकुर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान रहवासियों ने चेताया भी कि यदी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम जन आंदोलन करेंगे। एसडीएम राकेश परमार ने कहा अधिकारियों से बात कर इसका स्थानांतरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विधायक उषा ठाकुर ने कहा इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर इसका समाधान किया जाएगा।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

इंदौर में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स का प्रथम प्रदेश इकाई सम्मेलन संपन्न

देश में आने वाले समय में प्रदेश विकास कार्यो को लेकर नई पहचान बनाएगा - सीएम यादव

नगरीय निकायों के माध्यम से जनता के लिये समग्र विकास ही हमारा संकल्प - महापौर

इंदौर। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्यप्रदेश इकाई की पहली बैठक इंदौर में आयोजित की गई। बैठक में 16 नगरीय निकायों के 13 मेयर शामिल हुए। ऑल इंडिया काउसिंल ऑफ मेयर्स के मध्यप्रदेश इकाई अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव ने बताया ऑल इंडिया काउसिंल ऑफ मेयर्स के मध्यप्रदेश इकाई द्वारा प्रदेश के नगर निगम महापौर सदस्यों की वार्षिक बैठक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर ऑनलाईन जुड़े। इस एक दिवसीय सम्मेलन में शहरो के विकास से जुडे मुददो, बजट आवंटन, महापौर के अधिकारी बढाने संबंधित विषयो पर चर्चा हुई। साथ ही समस्त महापौर व अतिथयों द्वारा बीसीसी के पीछे स्थित युरेशिया गार्डन व ग्लोबल गार्डन में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, विधायक रमेश मेन्दोला, मधु वर्मा, गोलु शुक्ला, अतुल कोठारी, भाजपा नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिलाध्यक्ष श्रवण चांवडा, पूर्व महापौर डॉ. उमाशशि शर्मा, सभापति मुन्नालाल यादव, सुश्री शोभा पेठणकर, दीपक जैन टीनु, पुर्व सभापति अजयसिंह नरूका, भोपाल महापौर मालती राज, महापौर देवास गीता अग्रवाल, महापौर छिंदवाडा विक्रमसिंह अहाके, महापौर कटनी प्रीति सुरी, महापौर खंडवा अमृता यादव, महापौर ग्वालियर शोभा सिकरवार, महापौर रतलाम प्रहलाद पटेल, महापौर रीवा अजय मिश्रा, महापौर उज्जैन मुकेश टटवाल, महापौर सिंगरोली रानी अग्रवाल, समस्त महापौर परिषद सदस्य, बडी संख्या में पार्षदगण व अन्य अतिथि उपस्थित थे।

इंदौर ने सफाई में सात बार सरताज बनकर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई

इस सम्मलेन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली तरीके से जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर ने सफाई में सात बार सरताज बनकर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इंदौर नगर निगम ने बॉन्ड के जरिए जलूद में सोलर प्लांट की योजना से आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश की है। प्रदेश के दूसरे नगरीय निकाय यदि आत्मनिर्भर बनेंगे तो कल्याणकारी काम ज्यादा कर सकेंगे। सीएम यादव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में नगरीय निकायों ने अच्छी भूमिका निभाई। बैठक में जो भी योग्य प्रस्ताव तैयार होंगे, उसे सरकार लागू करने की कोशिश करेंगे।

तो जनता 25 साल तक याद करती है

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को सबसे ज्यादा अधिकार है। निकायों के मेयर थोड़ा सा साहस दिखाए, पारदर्शिता से काम करे टैक्स लगाकर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि हमें शिकायतें काफी मिली है। हम जांच नहीं कराते, यदि जांच करने लगे तो कई लोग कठघरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेयर का कार्यकाल एक जंपिंग पीरियड की तरह होता है। यदि, पांच साल के काम अच्छे से काम किए तो जनता 25 साल तक याद करती है।

हम सरकार के समक्ष रखेंगे

मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश के महापौरों का यह पहला सम्मेलन है। बैठक में जनप्रतिनिधियों के अधिकार, आय के स्त्रोत बढ़ाने जैसे कई विषयों पर जो भी सहमति बनेगी, उसे हम सरकार के समक्ष रखेंगे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा इंदौर में 6 चौराहों पर इन दिनों फ्लाईओवर का निर्माण शुरू

इंदौर। निर्माण कार्य , जिसे समय सीमा में पूरा करने के निर्देश विभागीय मंत्री ने दिए हैं। ये फ्लाईओवर मूसाखेड़ी, क्रिस्टल आईटी पार्क, सत्य साईं चौराहा, देवास नाका के अलावा बाणगंगा चौराहा पर निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग बाणगंगा के मानसिक चिकित्सालय परिसर को सुधारने के अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन भी निर्मित करेगा। अफसरों-जनप्रतिनिधियों की इस चर्चा में इंदौर-नेमावर को भी फोरलेन करने के अलावा इंगोनिया-उज्जैन रोड को पीथमपुर से नागदा तक जोडने का भी सुझाव दिया गया। वहीं अभी जो इंदौर से उज्जैन सिक्स लेन का काम चल रहा है उसे सिंहस्थ से पहले निर्मित कर देने की मांग भी विभागीय मंत्री से की गई। विभागीय मंत्री श्री सिंह ने ठेकेदारों से भी अलग से चर्चा की और उनकी समस्याओं को जाना। वन अनुमति में देरी, लंबित भुगतान, एवं भवन निर्माण की ड्राइंग व डिजाइन समय पर न मिलने जैसी समस्याओं पर तत्काल समाधान के लिए संबंधितों को निर्देशित किया गया। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में सडक़ और भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयसीमा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में देरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाएगी। मंत्री राकेश सिंह ने विलंब से चल रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई और समय सीमा निर्धारित करने तथा टाइम एक्सटेंशन नियमों को सख्त बनाने के निर्देश दिए। सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।

बैठक के बाद मंत्री श्री सिंह ने ठेकेदारों से अलग से चर्चा कर उनके सामने आ रही समस्याओं को समझा। वन अनुमति में देरी, लंबित भुगतान, एवं भवन निर्माण की ड्राइंग व डिजाइन समय पर न मिलने जैसी समस्याओं पर तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर-उज्जैन रेल सेक्शन में सांवेर रोड मुख्य जिला मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के धीमी गति से निर्माण पर अप्रसन्नता व्यक्त की, जिस पर श्री सिंह ने ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर-देपालपुर रोड को 4 लेन में परिवर्तित करने की मांग रखी। साथ ही इंगोरिया-उज्जैन रोड को पीथमपुर से नागदा तक विस्तार देने का सुझाव दिया। सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर-उज्जैन मार्ग के 6 लेन चौड़ीकरण कार्य को सिंहस्थ मेले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पूरा करने की आवश्यकता जताई। टोल प्लाजा पर लंबी कतारों की समस्या को देखते हुए टोल सेंसर कैमरों के शीघ्र सुधार के निर्देश दिए। देवास नाका चौराहे पर 6 लेन फ्लाईओवर के संबंध में श्री लालवानी ने कहा कि एमआर-2 रोड पर लैंडिंग सही ढंग से हो और जंक्शन का प्रावधान किया जाए। मूसाखेड़ी चौराहे पर 6 लेन फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए इसे चौड़ा करने और गड्ढों को एक सप्ताह के भीतर भरने के निर्देश मंत्री सिंह ने दिए। शंकर लालवानी और विधायक मधु वर्मा ने इंदौर-नेमावर मार्ग को 4 लेन बनाने की मांग की, क्योंकि इस सडक़ पर रोजाना 1000 से अधिक वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं।

बगैर अनुमति के बेच दिए छोटे-छोटे भूखंड, बना दी सडक़ और ड्रेनेज

इंदौर। नगर परिषद राऊ को क्षेत्रीय एसडीएम ने पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर विकसित होने वाली अवैध कॉलोनीको लेकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए किंतु एक साल में भी नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। पटवारी प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हो गया कि छोटे-छोटे प्लॉटों का विक्रय किया गया है और सडक़ तथा ड्रेनेज लाइन का निर्माण भी स्पष्ट नजर आ रहा है।राऊ नगर परिषद जहां एक और खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कॉलोनी बताकर उन्हें वैध करने के लिए प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर चुकी है, वहीं जिन जमीनों पर छोटे-छोटे प्लाटों का क्रय विक्रय हुआ और सडक़ के साथ ही ड्रेनेज निर्माण भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उस पर भी अभी तक एसडीओ के निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं की है। 1 साल पहले पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम राऊ ने सीएमओ राऊ नगर परिषद को निर्देश दिए थे कि उनके क्षेत्र की भूमि सर्वे नंबर 1016 रघुवर 0.251 हेक्टेयर पर नासिर पिता बहादुर अली शाह ने अवैध कॉलोनी विकसित करते हुए छोटे-छोटे भूखंडों में प्लॉटों का विक्रय किया है। उक्त व्यापवर्तित की गई भूमि पर नासिर शाह ने बिना सक्षम अनुमति के सीमेंट कांक्रीट रोड बनाई और उसके किनारो पर ड्रेनेज लाइन डालकर चेम्बरों का निर्माण भी किया है। क्षेत्रीय पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में सब प्रमाण जानकारी देते हुए बताया है कि उक्त जमीन पर कई आवासी मकान का निर्माण भी किया जा चुका है।

मामले की जांच के बाद एसडीएम ने नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए थे कि उक्त भूमि पर विकसित हो रही कॉलोनी के संबंध में दी गई अनुमतियों की प्रति विस्तृत प्रतिवेदन के साथ 12 मार्च तक उनके सम्मुख प्रस्तुत करें किंतु एक वर्ष पूरा व्यतित होने पर भी जबाब नही आया न आज तक नगर परिषद ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत की है। दूसरी और प्रशासनिक अधिकारियों की पोल भी इस प्रकरण से उजागर होती है कि वह नगर परिषद के जिम्मेदारों को खुली छूट दे रहे हैं, जिससे अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं जो नगर परिषद के संरक्षण में धीरे-धीरे उन्नति कर रही है किंतु उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अपर कलेक्टर को समाचार के माध्यम से कई बार इस क्षेत्र की जानकारी दी गई किंतु वे आज तक जानकारी नहीं होने की बात कह कर मामले को टालते रहे हैं यही नहीं पूर्व एसडीएम ने भी नगर परिषद के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया।

मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा

अवैध कॉलोनी के मामले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। नगर परिषद भी गुमराह करने वाली जानकारी देकर सत्यता को छुपाने का प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि जिला पंजीयक कार्यालय ने कलेक्टर के निर्देश पर 100 से अधिक अवैध कॉलोनी की सूची तैयार कर दी थी जिसमें राऊ की कई कालोनियां शामिल हैं, किंतु आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हर बार सुनवाई की बात कहकर मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

आयकर कानून के सरल होने से विवाद घटेंगे

देश में ऐसी सरल कर प्रक्रिया की अपेक्षा रही है कि कोई भी आदमी कर चुकाने के मामले में जमीनी और कागजी, दोनों ही स्तरों पर आत्मनिर्भर हो। नया कानून इस बड़ी अपेक्षा की पूर्ति करते हुए बड़ी परेशानियों से मुक्ति की राह प्रशस्त कर रहा है। ऐसे में चाहे असेसमेंट ईयर के बदले टैक्स ईयर जैसी शब्दावली तय करने की बात हो या सैलरी डिडक्शन से जुड़े तमाम प्रावधानों को एक सेक्शन में रखने की या खेती से जुड़ी आमदनी संबंधी प्रावधानों पर स्पष्टता लाने की, प्रस्तावित बिल सही ढंग से अमल में आए तो यह देश की टैक्स व्यवस्था को मजबूती देने के साथ नया भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को भी बदल देगा। चूंकि आयकर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया है, इसलिए यह आशा की जाती है कि वहां उस पर व्यापक एवं स्वस्थ विचार-विमर्श के दौरान उसे वास्तव में सरल रूप देने में मदद मिलेगी। इस अपेक्षा के साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोग स्वेच्छा से आयकर देने को प्रेरित हों और उनके मन में किसी तरह का भय न रहे। यह भी समय की मांग है कि सरकार आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने के उपाय करे।

ललित गर्ग

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को 64 साल पुराने आयकर कानून-1961 के सरलीकरण और इसमें चले आ रहे बेवजह के प्रविधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से नया इनकम टैक्स बिल-2025 पेश कर दिया। 622 पन्नों के इस विधेयक में 536 धाराएं शामिल हैं। जबकि आयकर कानून-1961 में 1647 पन्ने और 819 धाराएं रही है। इस विधेयक में कई पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर करदाताओं के लिए इसे आसान और पारदर्शी बनाया गया है। नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रिया को स्पष्ट, सहज, सरल और कानूनी उलझनों से मुक्त बनाना है जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों की संख्या कम हो। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। निश्चित ही नये आयकर कानून से टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलता के नए दौर की शुरुआत होगी, यह आयकर कानून का नया सूरज है, जो जटिलताओं एवं पेचिदगियों की जगह सरलता एवं सहजता की रोशनी बनेगा।मौजूदा आयकर कानून की तुलना में नया आयकर कानून शब्दों और धाराओं की संख्या के हिसाब से काफी छोटा है, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5.12 लाख शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द हैं। एक्ट के अलग-अलग चैप्टर भी 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं, नए कानून में 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। इन बदलावों का मकसद यह है कि लोग आसानी से आयकर के नियम समझ सकें और टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाए। यह बिल आयकर प्रावधानों को सरल और आसान बनाने के बड़े मकसद से जुड़ा है, जिसका फायदा आने वाले वर्षों में दिख सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रारंभ से ही कम-से-कम कानूनों एवं सरल-व्यवस्था के हिमायती रहे हैं।

दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में आर्थिक क्रांति का शंखनाद अनेक मोर्चे पर हो रहा है। न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बदली है बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल चुकी है। 1961 में बने आयकर कानून में बदलती जरूरत के मुताबिक नए-नए संशोधन होते रहे, जिससे इसकी जटिलता बढ़ती चली गई। यह जटिलता न केवल करदाताओं को उलझन में डालती थी बल्कि कानूनी प्रावधानों की कई तरह से व्याख्या अनेक उलझने एवं विवाद खड़ा करती रही है। इन जटिल होती परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि अपने देश में टैक्स को लेकर विवाद लगातार बढते गये। इन लगातार बढ़ते विवादों के कारण ही इसे दुनिया की टैक्स विवादों की राजधानी कहा जाने लगा। खासकर पिछले करीब डेढ दशक में यह ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। नौबत ऐसी आ गई कि 2023-24 तक टैक्स संबंधी मुकदमों में विवादित रकम बढ़कर 15.4 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिसका करीब 87 प्रतिशत हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा है। संभावनाएं हैं एवं सराहनीय भी है कि नये कानून के लागू होने से विवाद भी कम होंगे एवं जनता भी राहत की सांस लेगी। निश्चित ही यह कदम स्वागतयोग्य है। इस कानून को लाकर मोदी सरकार और विशेषतः वित्तमंत्री ने अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन किया है।आयकर कानून-1961 की जटिलताओं के कारण विवादों का अंबार लगा रहा है। जबकि आयकर विभाग को इन विवादों से कोई फायदा भी नहीं होता है क्योंकि इनमें जीत का उसका रेकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (ओईसीडी) की ओर से 34 देशों में टैक्स विवादों पर हुई एक स्टडी के मुताबिक 2015 में भारत में टैक्स विभाग को महज 11.5 प्रतिशत मामलों में ही जीत मिली थी। ओईसीडी देशों का औसत इस मामले में 65 प्रतिशत है। अवश्य ही यह स्थिति भारत के लिये चिन्ताजनक रही है। अब इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो नए आयकर कानून से कर संहिता अधिक सरल हो जाएगी और वह आयकर अधिकारियों के साथ आयकरदाताओं को भी राहत प्रदान करेगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि आयकरदाताओं को जटिल नियमों के साथ आसानी से समझ न आने वाली भाषा से छुटकारा मिले।

देश में ऐसी सरल कर प्रक्रिया की अपेक्षा रही है कि कोई भी आदमी कर चुकाने के मामले में जमीनी और कागजी, दोनों ही स्तरों पर आत्मनिर्भर हो। नया कानून इस बड़ी अपेक्षा की पूर्ति करते हुए बड़ी परेशानियों से मुक्ति की राह प्रशस्त कर रहा है। ऐसे में चाहे असेसमेंट ईयर के बदले टैक्स ईयर जैसी शब्दावली तय करने की बात हो या सैलरी डिडक्शन से जुड़े तमाम प्रावधानों को एक सेक्शन में रखने की या खेती से जुड़ी आमदनी संबंधी प्रावधानों पर स्पष्टता लाने की, प्रस्तावित बिल सही ढंग से अमल में आए तो यह देश की टैक्स व्यवस्था को मजबूती देने के साथ नया भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को भी बदल देगा। चूंकि आयकर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया है, इसलिए यह आशा की जाती है कि वहां उस पर व्यापक एवं स्वस्थ विचार-विमर्श के दौरान उसे वास्तव में सरल रूप देने में मदद मिलेगी। इस अपेक्षा के साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोग स्वेच्छा से आयकर देने को प्रेरित हों और उनके मन में किसी तरह का भय न रहे। यह भी समय की मांग है कि सरकार आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने के उपाय करे। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में डेढ सौ करोड की आबादी वाले देश में आयकर देने वालों की संख्या चार करोड़ से भी कम है। इनमें मुख्यतः वे ही हैं, जो नौकरीपेशा हैं। आयकर विभाग को इतना चुस्त एवं दुरस्त करने की जरूरत है कि जो समर्थ होते हुए भी आयकर नहीं देते हैं, ऐसे लोगों का पता लगाये। आखिर जो संपन्न किसान एक सीमा से अधिक आय अर्जित करते हैं, उन्हें आयकर के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? इसकी अनदेखी नहीं की जाए कि कृषि आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखने के नियम का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। बहुत से लोग काफी समय तक दवा के स्थान पर बीमारी ढोना पसन्द करते हैं पर क्या वे जीते जी नष्ट नहीं हो जाते? खीर को ठण्डा करके खाने की बात समझ में आती है पर बासी होने तक ठण्डी करने का क्या अर्थ रह जाता है? समर्थ लोगों को स्वैच्छा से आयकर देने के लिये तत्पर होना चाहिए। देश में आयकर का विषय विवादों से घिरा रहा है। अभी भी कुछ अर्थशास्त्री आयकर को दोहरा एवं गैर-जरूरी कराधान मानते हैं। लम्बे समय से ऐसे स्वर भी उभरते रहे हैं कि एक आम आदमी लगभग हर वस्तु और सेवा के लिये कर चुकाता है तो फिर उससे आयकर वसूलने की जरूरत क्यों है? भविष्य में इस पर भी सकारात्मक चिन्तन की अपेक्षा है। एक और बड़ी विसंगति का सामना आयकरदाता करता रहा है कि उसे आयकर विभाग हर मोर्चे पर सन्देह एवं शंका की नजर से देखता है। इसलिये जितना आवश्यक आयकर संबंधी नियम-कानून सरल करना है, उतना ही इस बात की अपेक्षा है कि आयकर विभाग लोगों से अनावश्यक रूप से न तो सवाल-जवाब करे और न ही किसी भूल-चूक पर उन्हें तंग करे। यह तब संभव होगा, जब आयकर अधिकारी आयकरदाताओं को संदेह की दृष्टि से देखना बंद करेंगे। उन्हें यह भी समझना होगा कि आयकर बचाने के उपाय अपनाने का मतलब कर चोरी करना नहीं होता। आयकर विभाग को उन कारणों का निवारण भी करना होगा, जिनके चलते लोग आय छिपाने के जतन करते हैं। इसी के साथ ऐसी भी व्यवस्था करनी होगी, जिससे आयकर का आकलन करने और उसकी वसूली में भ्रष्टाचार न होने पाए। आयकर विभाग को लोगों के विश्वास का उपभोक्ता नहीं अपितु संरक्षक बनना होगा। निश्चित ही नया आयकर कानून भारत की कर प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा। इससे करदाताओं को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आसानी होगी, कर प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

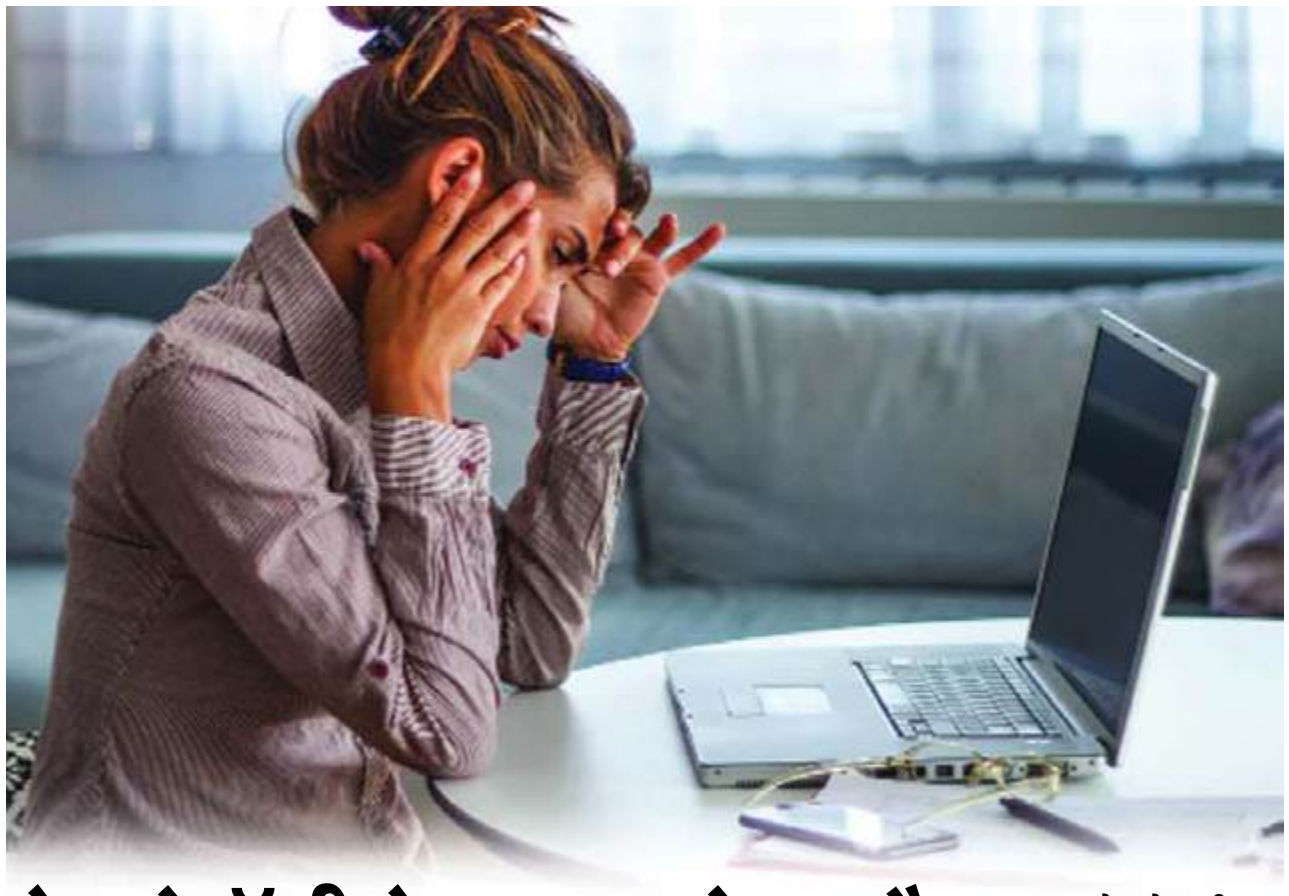

टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है स्ट्रेस तो इन आसान टिप्स की मदद से खुद को करें रिलैक्स

टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग आज के समय में तनाव का कारण बन रहा है, लेकिन आप इस तनाव को खुद से दूर करने के लिए कुछ आसान उपायों की मदद ले सकती हैं।

तनाव आज के समय में लोगों के जीवन का हिस्सा ही बन गया है। घर से लेकर ऑफिस में काम का बढ़ता बोझ, कमजोर पारिवारिक रिश्ते व बेहद जल्द सबकुछ पाने की चाह जीवन को तनावग्रस्त बनाती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज ऐसी भी है, जो स्ट्रेस को जन्म देती है और वह है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। वर्तमान में, किसी भी महिला का शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब वह टेक्नोलॉजी के संपर्क में ना आती हो। फोन से लेकर लैपटॉप में हम कई-कई घंटें बिताते हैं, लेकिन अंततः इनका अत्यधिक उपयोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं को जन्म देता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी आप टेक स्ट्रेस को खुद से दूर कर सकती हैं और इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ छोटे-छोटे टिप्स अपनाकर ऐसा आसानी से कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इन टिप्स के बारे में-

करें डिजिटली डिटॉक्स

खुद को तनावमुक्त रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद को कभी-कभी डिजिटली डिटॉक्स करें। स्क्रीन (आंखें स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं टिप्स) से बाहर आकर वास्तविक दुनिया का आनंद लें। मसलन, अगर संडे को आपकी छुट्टी होती है तो उस दिन अपने लैपटॉप को भी छुट्टी दें। कोशिश करें कि वह दिन आप अपने परिवार के साथ बिताएं और फोन, लैपटॉप व टीवी से दूरी बनाएं। इसके अलावा जब आप ऑफिस से घर आती है तो कम से कम एक घंटे के लिए फोन को बंद करके रखें। इससे भी आप खुद को अतिरिक्त टेक स्ट्रेस को दूर कर सकती हैं।

लें छोटे-छोटे ब्रेक

अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है तो हो सकता है कि इसके कारण आपको सिर में दर्द या फिर अन्य तरह के स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए इससे बचने के लिए आप काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। अगर संभव हो तो आप बीच में कुछ नैप भी ले सकती हैं। इससे भी आपका स्ट्रेस काफी कम होता है।

फोन को रखें बेड से दूर

टेक स्ट्रेस को दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जीवन में कुछ नियम तय करें। मसलन, जब आप रात में अपने बेड पर हों तो फोन को खुद से दूर रखें। इसके अलावा सुबह उठने के बाद सबसे पहले फोन को इस्तेमाल करने की आदत को बदलें। इस तरह के छोटे-छोटे टिप्स टेक स्ट्रेस को दूर रखने में मददगार होता है।

तय करें शेड्यूल

जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप उसे नियंत्रित रूप से ही इस्तेमाल करें। मसलन, आप लैपटॉप व फोन पर टाइम स्पेंड करने का शेड्यूल करें। साथ ही यह भी कोशिश करें कि आपका काम तय समय पर ही पूरा हो। इससे भी आप अपने तनाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं।

रिलैक्सिंग एक्टिविटी

यह सच है कि टेक्नोलॉजी को खुद से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप उसके नेगेटिव प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकती हैं। मसलन, अगर आपने पूरा दिन लैपटॉप पर काम किया है और अब आपको थकान व तनाव का अहसास हो रहा है तो काम खत्म करने के बाद आप कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी जरूर करें। मसलन, आप एक शॉवर लें या फिर अपना मनपसंद म्यूजिक सुनें। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा।

शैम्पू की खाली पड़ी बोतल से घर पर ऐसे तैयार करें धूपबत्ती स्टैंड

हम सभी बाजार से अलग-अलग शैम्पू की बोतल खरीद कर लाते हैं। जैसे ही शैम्पू खत्म होता है उसे कचरे के ढेर में फेंकते हुए। आपको बता दें इसकी मदद से आप बिना पैसा खर्च किए कमाल का सामान बना सकती हैं।

हम सभी के घरों एक नहीं कई ऐसे सामान आते हैं जो प्लास्टिक के डिब्बे में आते हैं। फिर चाहे बात करें फूड आइटम, क्लीनिंग और स्किन केयर प्रोडक्ट आज के समय ये सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के डिब्बे में आता है। सामान खत्म होने के बाद हम सभी इन डिब्बों को यूजलेस समझकर कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप इन डिब्बों का दोबारा और सही से इस्तेमाल कर घर की काफी यूजफुल सामान को क्रिएट कर सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप बेकार पड़े शैम्पू की बोतल से रिक्रिएट कर सकते हैं। होम डेकोर से लेकर पूजा स्थान पर इस्तेमाल होने वाले स्टैंड से लेकर डेकोरेशन आइटम्स को बाजार से खरीदना पसंद करते हैं। ये सामान देखने में जितने सुंदर होते हैं उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा व मूर्ति के सामने दीया और धूपबत्ती जलाने के लिए स्टैंड की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि आप सुंदर और यूनिक धूप बत्ती स्टैंड को खाली डिब्बे से तैयार कर सकती हैं। चलिए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

जरूरी सामान

- शैम्पू की बोतल (जो आपके पास मौजूद है)
- थर्माकोल
- क्ले • फेविकोल
- पेंट • ब्रश
- दपती • छोटे पत्थर
- छोटे प्लास्टिक का फूल और पत्ती
- मिट्टी का खिलौने वाला नन्हा घड़ा

स्टैंड बनाने का तरीका

- स्मोक धूप स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले बोतल के एक तरफ के ऊपरी हिस्से को काट लें।
- काटने के बाद ऊपर के हिस्से को काटकर वहां पर कैप लगाएं। इसके अलावा अंदर लगी पाइप को निकाल दें।
- अब थर्माकोल को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर बोतल के अंदर के हिस्से पर वॉल स्टैंड जैसा चिपकाएं।
- चिपकाने के बाद इसे कुछ देर सूखने दें। अब क्ले की मदद से छोटी चादर ,उसका थोड़ा सा किनारा नली की तरह बनाकर थर्माकोल के ऊपर रखकर ब्रश की मदद से अच्छे से चिपकाएं।
- इसके बाद छोटे-छोटे पत्थर को डिब्बे के नीचे वाले हिस्से में ग्लू की मदद से चिपका दें।
- अब सफेद पेंट की मदद से पत्थर और डिब्बे को पेंट कर दें।
- पेंट के सूखने के बाद ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके अंदर के हिस्से पर कलर करें।
- अब एक दपती लेकर उसके गोल व चौकोर टुकड़े करके डिब्बे के बाहर चिपका दें।
- इसके बाद ब्राउन पेंट करके उसे सेट होने के लिए दो से तीन घंटे के लिए छोड़ दें।
- एक स्पंज लेकर बाहर के हिस्से पर हल्का-हल्का टैप करें।
- इस प्रोसेस को करने के बाद आप अपने हिसाब से इसे सजा सकती हैं।
- अगर नहीं तो आप छोटे-छोटे प्लास्टिक के फूल और पत्ती को लगाकर पत्थर के ऊपर मिट्टी का छोटा सा बर्तन या घड़ा दें।

इस तरह से आप बिना अधिक पैसा खर्च किए घर पर डिमांडिंग और यूनिक स्मोकी धूप स्टैंड बनाकर तैयार कर सकती हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी:2025

हार्दिक पंड्या चैंपियंस ट्रॉफी में रच सकते हैं इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पंड्या चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. एक तो मध्यक्रम में उतरकर ताबड़तोड़ बैटिंग करना और फिर गेंदबाजी में टीम को हेल्प करना इस ऑल राउंडर खेल के चलते हार्दिक पर काफी दारोमदार रहेगा. 50 ओवर फॉर्मेट में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में वो गेंद और बल्ले दोनों से ही धमाल मचाएंगे. अगर उनका बल्ला उनके चिर परिचित अंदाज में रंग जमाता है तो हार्दिक चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में एक बड़ा कारनामा कर देंगे. पंड्या की निगाहें चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बनने पर टिकी होगी. ऐस होता है तो वो क्रिस गेल से 'सिक्सर किंग' का ताज छीन लेंगे और सौरव गांगुली की 'दादागिरी' का भी अंत कर देंगे.

गांगुली के नाम चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. 'दादा' के नाम से मशहूर गांगुली ने इस टूर्नामेंट में 13 मैचों की 11 पारियों में 73 के औसत से 665 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाए.

पंड्या को नंबर 1 बनने के लिए चाहिए 8 छक्के

चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में फिलहाल हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर बने हुए हैं. भारत के इस खिलाड़ी ने सिर्फ एक ही चैंपियंस ट्रॉफी (2017) खेली है. उन्होंने पांच मैचों की तीन पारियों में 105 रन बनाए. इस दौरान हार्दिक ने 10 छक्के लगाए थे. सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें 8 छक्कों की और जरूरत है. वैसे हार्दिक के लिए ये रिकॉर्ड तोडना बेहद आसान हो जाएगा. क्योंकि उनसे आगे जो भी बल्लेबाज हैं वो सभी रिटायर हो चुके हैं.

गेल से भी छीनेंगे 'सिक्सर किंग' का ताज

वेस्ट इंडीज के पूर्व धाकड़ खिलाड़ी क्रिस गेल लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं. वो चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 17 मैचों में 791 रन बनाते हुए 15 सिक्स लगाए हैं. तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन (14 सिक्स), चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन (12 सिक्स) और पांचवे नंबर पर 11 सिक्सेस के साथ इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड मौजूद हैं.

भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करारा झटका, चोटिल हुआ स्टार खिलाड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दुबई पहुंच गई है और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. भारत का पहला मैच बांग्लादेश से है, जो कि 20 फरवरी को खेला जाएगा. लेकिन टीम इंडिया को इससे ठीक पहले करारा झटका लगा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं. पंत को प्रैक्टिस के दौरान घुटने में चोट लगी है. हालांकि इस मामले पर अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर होगी. इससे पहले बांग्लादेश से मुकाबला होगा. एक खबर के मुताबिक ऋषभ पंत को घुटने में चोट लगी है. वे चोट की वजह से काफी परेशान दिखे. पंत चोट लगने के तुरंत बाद मैदान पर लेट गए. हालांकि इस दौरान भारतीय टीम के फिजियो उनके पास ही थी. पंत की चोट कितनी गंभीर है, इसका अभी पता नहीं चल सका है.

ऋषभ पंत का दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट हुआ था. इस एक्सीडेंट में उनको गंभीर चोट लगी थी. पंत के घुटने में काफी गंभीर चोट लगी थी. उन्होंने ठीक होने के बाद कमबैक किया. लेकिन अब फिर से घुटने पर चोट लग गई है.

सिनर और वाडा के बीच समझौते की आलोचना, वावरिंका-किर्गियोस समेत टेनिस खिलाड़ियों ने कही यह बात

लंदन

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर पर डोपिंग मामले में तीन महीने का प्रतिबंध लगाने के समझौते की टेनिस खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की है। सिनर और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के बीच निलंबन को लेकर समझौता हो गया है जिसका मतलब है कि इटली का यह खिलाड़ी पांच मई से फिर से खेल सकता है। इससे उनकी विश्व में नंबर एक रैंकिंग पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा तथा वह सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेल पाएंगे। पिछले साल मार्च में प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड के सेवन का दोषी पाए जाने वाले सिनर को कोई खिताब या पुरस्कार राशि भी नहीं गंवानी पड़ेगी।

तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टैन वावरिंका ने

एक्स पर लिखा, मैं अब साफ-सुथरे खेल में विश्वास नहीं करता। विंबलडन उपविजेता निक किर्गियोस ने एक्स पर कहा, टेनिस में निष्पक्षता मौजूद नहीं है। सिनर की टीम ने केवल तीन महीने का प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा दी। कोई खिताब नहीं खोया, कोई पुरस्कार राशि नहीं खोई। दोषी है या नहीं? टेनिस के लिए दुखद दिन।

विश्व के आठवें नंबर के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने मार्सिले ओपन के सेमीफाइनल में हारने के बाद कहा, मुझे उम्मीद है कि हर कोई वाडा के साथ चर्चा कर सकता है और अब से यानिक सिनर की तरह खुद का बचाव कर सकता है। विश्व के पूर्व नंबर एक ब्रिटिश खिलाड़ी टिम हेनमैन ने स्काई स्पोर्ट से कहा, उसने अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है और वह अगले तीन महीने तक एटीपी टूर में नहीं खेल पाएगा लेकिन फ्रेंच ओपन में खेलने का पात्र होगा। सिनर के लिए प्रतिबंध झेलने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था लेकिन यह इस खेल के लिए कड़वे घूंट की तरह है।

नोवाक जोकोविच और वासेक पोस्पिसिल द्वारा स्थापित प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन ने भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल पार्टियों की आलोचना करते हुए एक्स पर जारी बयान में कहा, प्रणाली कोई प्रणाली नहीं है। यह एक क्लब है। यह केवल अनुरूप सौदों, अनुचित व्यवहार और असंगत निर्णयों के लिए कवर है। इसमें पारदर्शिता की कमी और प्रक्रिया का अभाव है।

शहीद हुए जवान के बेटे का अंडर-19 टीम में चयन...

वीरेंद्र सहवाग ने बताई कहानी

नई दिल्ली, एजेंसी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को 6 साल पूरे हो चुके हैं. 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटक से लदे वाहन को आरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी थी. इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ. हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे.

सहवाग ने लिया था ये फैसला...

पुलवामा हमले के बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक दिल जीतने वाला फैसला लिया था. सहवाग ने पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली. सहवाग ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. राहुल सोरेंग और अर्पित सिंह झज्जर स्थित सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करते हैं. राहुल के पिता विजय सोरेंग और अपित सिंह के पिता राम वकील उस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे. राहुल सोरेंग तो अब क्रिकेट की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं. राहुल सोरेंगे का चयन हाल ही में हरियाणा अंडर-19 टीम में हुआ है. इसकी जानकारी वीरेंद्र सहवाग ने खुद दी है.

वीरेंद्र सहवाग ने पुलवामा अटैक की छठी बरसी पर एक मार्मिक पोस्ट शेयर किया. सहवाग ने लिखा, इस दुखद दिन को 6 साल हो गए है. हमारे बहादुर जवानों के शहादत की भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन राहुल सोरेंग ह्य/श शहीद विजय सोरेंग और अर्पित सिंह शहीद राम वकील पिछले 5 सालों से सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में हैं, जो सबसे संतोषजनक अहसासों में से एक है. राहुल को हाल ही में हरियाणा अंडर-19 टीम में चुना गया है. सभी बहादुरों को नमन.

वीरेंद्र सहवाग की यह पोस्ट न केवल राहुल सोरेंग की उपलब्धि का जश्न मनाती है, बल्कि भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके परिवारों का समर्थन करने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है. राहुल की जर्नी आशा की किरण है और यह याद दिलाती है कि कैसे एक सार्थक पहल युवा प्रतिभाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकती है. राहुल ने स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग की है और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपने क्रिकेटिंग स्किल को निखारा है. उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने अब उन्हें हरियाणा अंडर-19 टीम में जगह दिलाई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

प्रदेश में 5 वर्षों में मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लिये बनेंगे 10 लाख आवास

50 हजार करोड़ रुपये का होगा निवेश

इंदौर। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये 10 लाख आवासों का निर्माण किया जायेगा। इन आवासों के निर्माण में 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा। इस राशि में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमानित अनुदान राशि 23 हजार 25 करोड़ रूपये प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही परिवारों के लिये हर मौसम के अनुकूल आवासों के निर्माण के साथ समुचित अधोसंरचना जैसे- सड़क, जल प्रदाय, सीवेज, पार्क तथा सामाजिक अधोसंरचना के रूप में आंगनवाड़ी प्राथमिक शाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकसित किये जायेंगे। राज्य शासन द्वारा सभी पात्र हितग्राही परिवारों को आवास दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत अब तक करीब 2 लाख 90 हजार हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

हितग्राहियों को 4 घटकों में किया जायेगा लाभान्वित

पीएमएवाई-यू 2.0 में जिन 4 घटकों में लाभान्वित किया जायेगा, उनमें आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही होंगे। बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही अपनी स्वयं की भूमि पर आवास का निर्माण कर सकेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर/डेवलपर्स द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान किया जायेगा। इसके अंतर्गत निजी डेवलपर द्वारा परियोजना में हितग्राहियों द्वारा आवास क्रय करने पर रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर (आर.एच.व्ही.) प्रदान किया जायेगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ए.आर.एच.) के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर और निराश्रितों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिये किराये के आवास बनाकर उपलब्ध कराये जायेंगे। इन्ट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एस.) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा।

योजना के दिशा-निर्देश अनुसार होगा क्रियान्वयन

पीएमएवाई-यू 2.0 में सिंगल वूमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, कल्याण महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्प संख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरियता दी जायेगी। इसी के साथ योजना में सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना के विभिन्न कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और बस्ती एवं चाल के निवासियों पर योजना के माध्यम से विशेष ध्यान दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जायेगी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान कम करने के लिये पूर्वानुसार क्रॉस सब्सिडी मॉडल को क्रियान्वित किया जायेगा। भूमिहीन पात्र हितग्राही परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति भी दी गई है। बीएलसी वर्ग के हितग्राहियों को प्रति आवास 2 लाख 50 हजार रूपये अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी परिवारों द्वारा आवास के निर्माण के चरणों का स्वयं जियो टैगिंग का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अविवाहित कमाऊ वयस्क सदस्यों को पृथक से लाभ प्रदान करने के प्रावधान को समाप्त कर एक हितग्राही परिवार में पति-पत्नी, अविवाहित बेटे-बेटियों को शामिल किया गया है।

पीएम आवास योजना शहरी के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रथम चरण में मध्यप्रदेश अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से देश में दूसरे स्थान पर रहा है। पहले चरण में 9 लाख 45 हजार आवासों में से वर्तमान में 8 लाख 33 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। इन आवासों की स्वीकृति अनुदान राशि 19 हजार 400 करोड़ में से केन्द्र और राज्य शासन, द्वारा 18 हजार 700 करोड़ रूपये की राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है।

नवाचार से विश्वस्तरीय बनेगा लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

आपूर्ति आसान, लागत पर लगेगी लगाम: डॉ मोहन

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा।मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आगामी वर्षों में इससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार पोर्ट टर्न अराउंड समय को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे राज्य की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को सुधारा जा सकेगा।

साथ ही पीसीएस-वन प्रणाली से ई-डिलीवरी आदेशों को पेश किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेटेट लैब बनाई जाएंगी, जिससे उत्पाद सुरक्षा नियमों और गुणवत्ता मानकों खरे उतर सकेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डोर (आरएफआईडी) जैसे तकनीकी नवाचार सुरक्षा को बढ़ाएंगे और माल की आवाजाही भी तेज होगी। साथ ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म के समावेश से लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में डेटा का आदान-प्रदान सरल और तेज बनेगा। पॉलिसी के नवाचारों में ग्रीन कार्ड योजना भी शामिल है, जो ऐसे लॉजिस्टिक्स संचालकों को शीघ्र मंजूरी देगी, जो ग्रीन-ट्रांसपोर्टेशन को अपनाएंगे। अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार 20 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित कर रही है। इससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो माल ढुलाई को सुगम बनाएंगे। परिवहन लागत कम होने से व्यवसायियों का लाभ बढ़ेगा और प्रदेश में अधिक निवेश आकर्षित होगा।

निर्यात क्षमता बढ़ाने विकसित होगा विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का एक महत्वपूर्ण अंग राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाना भी है। इसके लिए पॉलिसी में निर्यात पार्क विकसित किए जाने के प्रावधान शामिल किये गए हैं। इन पार्कों के विकासक को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अधिकतम 40 करोड़ रुपए अथवा प्रति एकड़ 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। निर्यातकों के लिए सामान्य प्र-संस्करण सुविधाओं की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिये परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रीलायजेशन को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन की शून्य तरल प्रणालियों और केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। पॉलिसी में निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा, निर्यात-उन्मुख इकाइयों की दक्षता बढ़ाना और सुदृढ़ निर्यातोन्मुख लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। पॉलिसी के उद्देश्यों में निर्यात की मात्रा बढ़ाना, ÷मेड इन मध्यप्रदेश÷ उत्पादों के निर्यात मूल्य में वृद्धि करना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन भी शामिल है। लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से व्यापारियों और उद्यमियों को सीधा लाभ होगा। वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में लाखों नई नौकरियां उपलब्ध होंगी। विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। साथ ही किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर परिवहन और भंडारण सुविधाएं मिलेंगी।

महाकाल मंदिर में शुरू हुआ 10 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव

उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का पर्व नौ दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह उत्सव पूरे 10 दिन चलेगा, क्योंकि इस बार एक खास तिथि दो दिनों तक रहेगी. मंदिर के पुजारी के अनुसार, इस साल फाल्गुन कृष्ण सप्तमी दो दिन (19 और 20 फरवरी) को पड़ रही है, इसलिए शिव नवरात्रि उत्सव एक दिन अधिक रहेगा, ऐसे में सोमवार (17 फरवरी) को विशेष भस्म आरती के साथ महाकाल मंदिर में शिवरात्रि का शुभारंभ हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। जानकारी के अनुसार, इस दौरान बाबा महाकाल के अलग-अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे पंचमी से त्रयोदशी तक विशेष पूजन-अर्चन किया जाएगा हर दिन सुबह आठ बजे कोटितीर्थ कुंड स्थित कोटेश्वर महादेव का पूजन होगा इसके बाद गर्भगृह में भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक होगा और 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्री पाठ किया जाएगा वहीं दोपहर एक बजे भोग आरती होगी, इसके बाद तीन बजे संध्या पूजा के बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाएगा।

शिव नवरात्रि में बदलेगा पूजन का समय

बता दें शिव नवरात्र में अभिषेक-पूजन के विशेष अनुक्रम के कारण श्री महाकालेश्वर मंदिर में भोग आरती और संध्या पूजन का समय बदलेगा फिलहाल महाकाल मंदिर में सुबह 10 बजे भोग आरती संपन्न किया जाता है और शाम पांच बजे संध्या पूजन होता है, लेकिन शिव नवरात्र के नौवों दिन दोपहर एक बजे भोग आरती और दोपहर तीन बजे संध्या पूजन होगा। शिव नवरात्रि के पहले दिन महाकाल का चंदन श्रृंगार होगा दूसरे दिन शेषनाग श्रृंगार, तीसरे दिन घटाटोप श्रृंगार, चौथे दिन छबीना (राजकुमार) श्रृंगार, पांचवें दिन होल्कर रूप श्रृंगार, छठे दिन मनमहेश रूप श्रृंगार, सातवें दिन उमा महेश श्रृंगार, आठवें दिन शिवतांडव श्रृंगार, नौवें दिन सप्तधान श्रृंगार होगा। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर दिनभर जलधारा से महाकाल का अभिषेक होगा और रातभर बाबा महाकाल का विशेष पूजन और अभिषेक होगा अगले दिन 27 फरवरी को सुबह भगवान के सप्तधान्य श्रृंगार और सेहरे के दर्शन होंगे, दोपहर 12 बजे भस्म आरती होगी, इस दौरान मंदिर के पट 44 घंटे खुले रहेंगे, यह साल में एकमात्र मौका होता है जब दोपहर में महाकाल की भस्म आरती होती है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक गोपाल गावंडे द्वारा पंकज प्रिंटर्स एण्ड पैकेजिंग एल.यू.एन 22 सेक्टर एफ सांवेर रोड़, इण्डस्ट्रीयल एरिया इंदौर म.प्र. एवं जी -1 कॉस्मिक रीजेंसी 117 गोकुल नगर कनाडिया इंदौर म.प्र. से प्रकाशित
संपादक गोपाल गावंडे (पी.आर.बी.) एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार (सभी विवादो का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)